आकाशवाणी केन्द्र शिमला

12.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1500बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। शिमला में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

*अभी युवा पीढ़ी से मैं यह ही कहना चाहता हूं की आने वाले समय में जो नशा है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे है कि चुनौती बड़ी है इस लड़ाई का हम मिलझुल कर सामना करना है खास चिट्टे दू रहे चिट्टा ऐसा जहर है जिसके खिलाफ सरकार तो लड़ाई लड़ रही है लेकिन समाज के सभी वर्ग इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे तभी हम सफल होंगे।*

प्रतिमा

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कल किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं के भाग लेने का कार्यक्रम है।

जीएसटी

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगली पीढ़ी के जी.एस.टी. सुधारों के साथ, सरकार ने कृषि उपकरणों पर जी.एस.टी. दरों को कम करके किसानों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि छोटे ट्रैक्टर पर किसानों को लगभग 23 हज़ार रूपए की बचत होगी।

*कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे छोटे टैक्टर पर 23 हजार रुपये बचेंगे। 35 हॉर्स पावर पर के टैक्टर पर लगभग 43 हजार रुपये बचेंगे और बड़े टैक्टर पर भी लगभग 65 हजार रुपया तक बचेंगे। अलग–अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी हम आभारी हैं किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है।*

शिक्षा मंत्रालय – यूपीआई

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों से प्रवेश व परीक्षा शुल्क एकत्र करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफे़स–यू.पी.आई. अपनाने का आग्रह किया है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एन.सी.ई.आर.टी., सी.बी.एस.ई, के.वी.एस. और एन.वी.एस. जैसी स्वायत्त संस्थाओं को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्कूलों में वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित

करने के लिए यू.पी.आई. अपनाने के लिए जोर दिया है। मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नकद भुगतान से डिजिटल भुगतान में बदलाव से स्कूल प्रशासन का आधुनिकीकरण होगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा।

<u>निजी बस ऑपरेटरों</u>

निजी बस ड्राइवर–कंडक्टर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कल 13 अक्तूबर को राजधानी शिमला में बसें न चलाने का निर्णय लिया है। यूनियन का कहना है कि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है जिससे बस ऑपरेटरों को भारी नुकसान हो रहा है। यूनियन के प्रधान रूप लाल ठाकुर ने कहा कि बढ़ती डीजल की कीमतें, टैक्स, और रूट परमिट को लेकर जारी असमानता के कारण निजी बस ऑपरेटरों को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बसों को शहर के अंदर प्रवेश न करने देने की मांग सरकार से की गई है ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके।

<u>चम्बा पर्यटन</u>

चम्बा ज़िले को धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष कार्य योजना के तहत काम करेगी। ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि ज़िले में कई अनछुए पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें विकसित किया जाएगा।